effect from 1985-86. The expenditure on account of these courses was follows:

Budget Estimates (in lakhs of Rs.)		
1985-86	1986-87	1987-88
60.77	82.33	100.00

The amount spent so far (from 1-8-86 to 31-7-87) on the compul sory training of IPS officers is Rs. 2.69 lakhs.

Sainik Schools in Madhya Pradesh

3097. SHRI AJIT P. K. JOGI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) what is the number of Sainik Schools and students studying in them in Madhya Pradesh;

(b) whether there is any proposal to set up more Sainik Schools in Madhya Pradesh or in any other State of the Country; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ PATIL): (a) There is one Sainik School in Madhya Pradesh at Reva. As on 31st July, 1987, 487 students were studying in the School.

(b) A Sainik School is established on the specific request of a State Government/Union Territory Administration, as the entire capital expenditure and a major portion of the recurring expenditure of the school, has to be borne by them.

No proposal has been received from the Government of Madhya Pradesh for setting up of more Sainik Schools. However three other States have shown interest in opening new schools. But, their detailed proposals have not been received.

(c) Does not arise.

गरीबों का उत्थान

3098. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाये जाने की सम्भावना है और इस पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की सम्भावना है ;

(ख) इस संबंध में अब तक किस सीमा तक कामयाबी हासिल की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि बिहार जैसे विभिन्न राज्यों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को केवल कागजों पर ही लागू किया जा रहा है और यदि हां, तो क्या उसका कोई मूल्यांकन किया गया है यदि हां, तो कितने व्यक्ति दोबारा गरीबी की रेखा से नीचे चले गए हैं ; और

(घ) इस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में क्या विभिन्न तकनीक अपनाये जा रहे है और किन तरीकों से लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) अनुमान है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता जो 1984–85 में अनुमानत: 36.9 प्रतिशत थी, घट कर 25.8 प्रतिशत रह जाएगी । निरपेक्ष रूप में, गरीब व्यक्तियों की संख्या जो 1984–85 में 273 मिलियन थी, घटकर 1989–90 में 211 मिलियन रह जाने की सम्भावना है । एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम गरीबी दूर करने के विशिष्ट कार्य क्रम हैं, जिनके लिए 70.25 करोड़ रु० का आवंटन किया गया है ।

(ख) नीचे सारणी में 1985–86 और 1986–87 में हुई प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी दी गई है।

(करोड़ रु० में)

क्र०सं०	कार्यक्रम	1985–86		1986–87	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	407.36	441.10	543.83	604.37
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार का०	457.53	531.95*	457.50	598.88*
3.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कायक्रम	499.00	435.07	633.65	616.99

*खाद्यान्नों की लागत सहित।

(ग) बिहार राज्य में प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई प्रगति के विषय में सारणी में निम्न जानकारी दी गई है :—

	इकाई	1985–86	1986–87
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
1. कुल आंवटन राशि	लाख रु०	5248.41	7097.72
2. जन-उपयोग	—वही—	4954.45	7501.15
3. सहायता प्राप्त कुल परिवार			
(क) लक्ष्य	संख्या	310000	460000
(ख) उपलब्धि	संख्या	421135	524546
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम			
1. कुल आंवटन राशि	लाख रु०	6548	6468
2. जन-उपयोग	—वही—	7065.17	9405.61
3. रोजगार के उत्पन्न किए गए अवसर			
(क) लक्ष्य	लाख कार्य दिवस	316	290
(ख) उपलब्धि	—वही—	416.27	369.63
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम			
1. आंवटन राशि	लाख रु०	7149.20	6973
2. जन-उपयोग	—वही—	4658.26	8385.88

	इकाई	1985-86	1986-87
3. रोजगार के सृजित अवसर			
(क) लक्ष्य	लाख श्रम दिवस	281	262
(ख) उपलब्धि	—वही—	232.73	328.66

ऊपर का सारणी से स्पष्ट है कि एक महत्वपूर्ण प्रगति सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान बिहार राज्य में विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत की गई है। उन व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, जो गरीबी की रेखा से नीचे है।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए लोगों को इस काम में शामिल करने पर विशेष बल दिया गया है। योजना में आयोजन और विकास प्रशासन के विकेन्द्रीकरण के लिए कारगर कदम उठा कर और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वैच्छिक अभिकरणों की सहभागिता में वृद्धि करके यह कार्य करने का प्रस्ताव है।

बैंकों में राजभाषा का प्रयोग

3099. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव। क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीयकृत बैंक और उनके अध्यक्षों तथा प्रबंध निदेशकों के नाम क्या-क्या हैं ;

(ख) इन बैंकों में से प्रत्येक बैंक की कितनी कितनी शाखायें हिन्दी भाषी राज्यों के "क" क्षेत्र में स्थित हैं और उनमें कितनी शाखाओं में शत प्रतिशत कार्य राजभाषा हिन्दी में किया जाता है और कितनी शाखाओं में क्रमशः 75,50 तथा 25 प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जाता है ;

(ग) इस संबंध में "ख" क्षेत्र की क्या स्थिति है और जहां तक कार्य के राजभाषा हिन्दी में किए जाने का संबंध है देश के सभी बैंकों में सौराष्ट्र चोटी पर है और इस संबंध में दूसरा स्थान महाराष्ट्र ने लिया है ; और

(घ) इन बैंकों की कितनी पत्र-पत्रिकायें (गृह पत्रिका समेत) राजभाषा में निकलती हैं तथा कितनी और पत्रिकाओं का हिन्दी में निकाले जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों और उनके मुख्य कार्यालयों के नाम अनुबंध में दिए गए हैं। [देखिए परिशिष्ट CXLIII, अनुबंध संख्या 120]

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31 दिसम्बर, 1986 को "क" और "ख" क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों की शाखाओं की संख्या और इन क्षेत्रों में हिन्दी में किए जाने वाले काम का ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-II और अनुबंध-III में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट CXLIII अनुबंध संख्या 121] चूंकि शाखाओं की संख्या की तारीख और हिन्दी में किए जाने वाले काम की प्रतिशतता के अनुसार उनका ब्यौरा दर्शाने वाली तारीख एक समान नहीं है, इसलिए संभव है कि जोड़ मेल न खाए।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, "ख" क्षेत्र के वास्ते वर्ष 1985 का भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर राजभाषा शील्ड का परिणाम निम्नानुसार था :—

प्रथम केनरा बैंक
यूनियन बैंक आफ इंडिया
द्वितीय स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर